

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
भा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग - 2

देहरादून : दिनांक : 25 फरवरी, 2008

विषय:- कुटुम्ब न्यायालयों हेतु वित्तीय वर्ष 2007-2008 में अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-269/आड/07-08-लेखा अनुभाग, दिनांक 28.1.2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 7-दो(2)/XXXVI(1)/2/2007-1-दो(2)/07, दिनांक 16.7.2007 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कुटुम्ब न्यायालयों के उपसहयोगी मानक मद संख्या-06-अन्य भत्ते एवं मानक मद संख्या-15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद के सम्प्रति बजट में कोई धनराशि अवशेष न होने के कारण तथा वर्तमान में आवश्यकता के दृष्टिगत सैलन बी०एम०-15 के स्तम्भ-1 में अंकित मद संख्या-14-कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय में अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से बी०एम०-15 के स्तम्भ-5 में अंकित मद संख्या-06-अन्य भत्ते में रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपये मात्र) एवं मद संख्या-15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद में रु० 10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) अर्थात् कुल रु० 2,10,000/- (दो लाख दस हजार रुपये मात्र) की धनराशि को व्यावर्तित कर व्यय किये जाने की महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i) प्रत्येक माह होने वाले व्यय की सूचना प्रपत्र बी०एम०-13 में अंकित कर उपलब्ध कराया जाय ।

(ii) उक्त धनराशि बजट मैनुअल के सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(iii) यह भी सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त अनुदान से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय ।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजक-105-सिविल और सेरान्स न्यायालय-03-जिला तथा सेशन न्यायाधीश-04-पारिवारिक न्यायालय-00-" के अन्तर्गत सैलन बी०एम०-15 के स्तम्भ-5 में अंकित प्राथमिक इकाईयों से किया जायेगा ।

4. यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या यू०ओ० 1587/XXVII(5)/2008, दिनांक 21.2.08 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

सैलनक : बी०एम०-15

भवदीय,

(आर०डी०पालीवाल)

सचिव ।

संख्या : 38-दो(2)/XXXVI(1)/2007-08-1-दो(2)/07-तद्विनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
- 2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
- 3- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
- 4- एन०आई०सी०/सम्बन्धित सहायक/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)

अपर सचिव ।

निम्नलिखित अधिकारी का नाम- महानिदेशक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल ।

प्रशासनिक विभाग का नाम- न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

वर्तमान प्रशासन तथा सेवा संबंधी कार्य का विवरण

1	2	3	4	5	6	7	अन्य विवरण
2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनोत्तर-105-सिविल एवं सेशन न्यायालय-04-पारितोषिक न्यायालय-00-14-कार्योत्तर इलेक्ट्रॉनिक न्याय कारोबार माहिदपुर का क्रम	1500		1500	2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनोत्तर-105-सिविल एवं सेशन न्यायालय-04-पारितोषिक न्यायालय-00-15-इलेक्ट्रॉनिक न्याय एवं पेटेंट आदि को छोड़कर	749 260	1290	क-वचन होने के कारण । ख- प्रविधान कम एवं आवश्यकता अधिक होने के कारण ।
1500			1500	210	1009	1290	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बचत अनुअल के परिच्छेद 150-156 में उल्लिखित प्रविधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया गया है ।

उत्तराखण्ड शासन

वित्त विभाग

संख्या-1387-क/वित्त अनुभाग-5/2008

देहरादून : दिनांक : 21 फरवरी, 2008

पुनर्विनियोग स्वीकृत

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),

उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड,

भाजरा, देहरादून ।

एन०एच०एच०वित्त,

अपर सचिव, वित्त ।

संख्या- 38-चौ(2)/XXV(1)/2007-08-1-चौ(2)/07-सदरिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आदेशक कार्यकारी हेतु प्रेषित -

1- महानिदेशक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल ।

2- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

3- जस्टिस कोषाधिकारी, नैनीताल ।

4- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन ।

5- मार्च बुक ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)

अपर सचिव